

ALL INDIA BAR EXAMINATION -XX (Set Code-A)

1. If a bailiff executes an eviction based on a civil court order later declared void for lack of jurisdiction, what protection does Section 78 of the Indian Penal Code provide? / यदि कोई बैलिफ किसी सिविल न्यायालय के आदेश के आधार पर बेदखली करता है, जिसे बाद में अधिकार क्षेत्र के अभाव में शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 78 क्या सुरक्षा प्रदान करती है?

- (A) The bailiff is punishable as the order was invalid from the beginning / बैलिफ दंडनीय है क्योंकि आदेश शुरू से ही अमान्य था।
- (B) The bailiff can be punished only with a reduced penalty / बैलिफ को केवल कम दंड से ही दंडित किया जा सकता है।
- (C) The bailiff is exempt if he acted in good faith under the order / यदि बैलिफ ने आदेश के तहत सद्व्यवनापूर्वक कार्य किया है, तो उसे छूट प्राप्त है।
- (D) The bailiff is required to compensate the evicted person / बैलिफ को बेदखल व्यक्ति को मुआवजा देना आवश्यक है।

Ans. [C]

2. Under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, what is the maximum number of consecutive days an offender may be kept in solitary confinement at a time? / भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत, एक अपराधी को एक समय में अधिकतम कितने दिनों तक एकांत कारावास (परिरोध) में रखा जा सकता है?

- (A) Seven / सात
- (B) Ten / दस
- (C) Fourteen / चौदह
- (D) Twenty-one / इक्कीस

Ans. [C]

3. According to the Motor Vehicles Act, 1988, what is the fixed amount of compensation payable in the event of death caused by a motor vehicle accident under no-fault liability? / मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, मोटर वाहन दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में दोष रहित दायित्व के अंतर्गत देय मुआवजे की निश्चित राशि क्या है?

- (A) Twenty-five thousand rupees / पच्चीस हजार रुपये
- (B) Fifty thousand rupees / पंचास हजार रुपये
- (C) One lakh rupees / एक लाख रुपये
- (D) Seventy-five thousand rupees / पचहत्तर हजार रुपये

Ans. [B]

4. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). des Assertion (A):

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

An employee can be deemed to be in continuous service for one year only if he has worked for 365 days in the preceding twelve months, without any interruption. / अभिकथन (A) : किसी कर्मचारी को एक वर्ष तक निरंतर सेवा में तभी माना जा सकता है जब उसने पिछले बारह महीनों में बिना किसी रुकावट के 365 दिन काम किया हो।

Reason (R) : Under the Payment of Gratuity Act, 1972, continuous service may also include periods of interruption due to sickness, accident, leave, lay-off, strike, or lock-out not caused by the employee's fault. / कारण (R) : उपदान संदाय (ग्रेच्युटी भुगतान) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत, निरंतर सेवा में बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, छंटनी, हड्डताल या तालाबंदी के कारण रुकावट की अवधि भी शामिल हो सकती है, जो कर्मचारी की गलती के कारण नहीं हुई हो।

In the context of the above assertion and reason under the Payment of Gratuity Act, 1972, which one of the following is correct? / उपदान संदाय (ग्रेच्युटी भुगतान) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपर्युक्त अभिकथन और कारण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A). /(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A). /(A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) (A) is true, but (R) is false. /(A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
- (D) (A) is false, but (R) is true. /(A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

Ans. [D]

5. Read the following statements and choose the correct option. / निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।

Statement 1: Under the Indian Penal Code, if a person harbours an offender who has escaped custody for an offence punishable with imprisonment up to 3 years, he shall be punished with imprisonment up to 7 years. / कथन 1 : भारतीय दंड संहिता के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराधी को शरण देता है जो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए हिरासत से भाग गया है, तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा।

Statement 2: The law provides an exception for harbouring or concealing by the husband or wife of the offender. / कथन 2 : कानून अपराधी के पति या पत्नी द्वारा शरण देने या छिपाने के लिए एक अपवाद प्रदान करता है।

[Click Here to Buy Linking Publications](#)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOS



In the context of the above statements under the Indian Penal Code, which one of the following is correct ? / भारतीय दंड संहिता के तहत उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

- (A) Both Statements 1 and 2 are false / कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं
- (B) Only Statement 1 is true / केवल कथन 1 सत्य है
- (C) Only Statement 2 is true are fals / केवल कथन 2 सत्य है
- (D) Both the Statements are true / दोनों कथन सत्य हैं

Ans. [C]

6. If a person attempts an offence punishable with a maximum of 10 years imprisonment, what is the maximum years of imprisonment that can be imposed under Section 62 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023? / यदि कोई व्यक्ति अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का प्रयास करता है, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 62 के अंतर्गत अधिकतम कितने वर्ष का कारावास दिया जा सकता है ?

- (A) Five years / पाँच वर्ष
- (B) Seven years / सात वर्ष
- (C) Ten years / दस वर्ष,
- (D) Three years / तीन वर्ष

Ans. [A]

7. A juvenile aged 14 years is brought before the court for an offence not punishable with death or imprisonment for life. Under which provision of the Code of Criminal Procedure, 1973, will the case primarily fall? / 14 वर्ष की आयु के एक किशोर को न्यायालय में ऐसे अपराध के लिए लाया जाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। यह मामला मुख्यतः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के किस प्रावधान के अंतर्गत आएगा ?

- (A) Section 27 M / धारा 27
- (B) Section 125 / धारा 125
- (C) Section 302 / धारा 302
- (D) Section 482 / धारा 482

Ans. [A]

8. Under Section 290 (1) of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, within how many days from the date of framing of charge can an accused file an application for plea bargaining? / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 290 (1) के अंतर्गत, आरोप तय होने की तिथि से कितने दिनों के भीतर कोई अभियुक्त सौदा अभिवाकृ के लिए आवेदन दायर कर सकता है?

- (A) 15
- (B) 30
- (C) 45
- (D) 60

Ans. [B]

9. Under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, if a person is ordered to pay a fine of ₹ 4,000 but fails to do so, what is the maximum simple imprisonment the court may impose on the defaulter? / भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत, यदि किसी व्यक्ति को ₹ 4,000 का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो न्यायालय द्वारा चूककर्ता पर अधिकतम कितना साधारण कारावास लगाया जा सकता है ?

- (A) One year / एक वर्ष
- (B) Two months / चार महीने
- (C) Four months / दो महीने
- (D) Six months / छह महीने

Ans. [B]

10. According to Section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, what is the minimum period of practice as an advocate, required to be considered eligible for appointment as a Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor? / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 के अनुसार, लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र माने जाने हेतु अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय की स्थूनतम अवधि कितनी है ?

- (A) 3 years / 3 वर्ष
- (B) 5 years / 5 वर्ष
- (C) 7 years / 7 वर्ष
- (D) 10 years / 10 वर्ष

Ans. [C]

11. Under the Indian Evidence Act, 1872, when can facts that are otherwise irrelevant be considered relevant? / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत, ऐसे तथ्य जो अन्यथा अप्रासंगिक हैं, उन्हें कब प्रासंगिक माना जा सकता है ?

- (A) Only when they prove the guilt of the accused directly / केवल तभी जब वे अभियुक्त के अपराध को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करते हों
- (B) Only when they form part of a dying declaration / केवल तभी जब वे मृत्युकालिक कथन का भाग हों
- (C) When they are inconsistent with a fact in issue or relevant fact / जब वे किसी विवाद्यक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य से असंगत हों
- (D) When they are part of an admission made in writing / जब वे लिखित रूप में की गई स्वीकृति का भाग हों

Ans. [C]

12. What condition must be satisfied for prior evidence to be relevant under Section 33 of the Indian Evidence Act, 1872?

[Click Here to By Linking Publications](#)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOS

www.LinkingLaws.com

Linking Laws Tansukh Sir

Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 33 के अंतर्गत पूर्व साक्ष्य के प्रासंगिक होने के लिए कौन-सी शर्त पूरी होनी चाहिए ?

- (A) The evidence must have been recorded in the presence of a jury. / साक्ष्य जूरी की उपस्थिति में दर्ज किया गया होगा ।
- (B) The proceeding was between the same parties or their representatives in interest. / कार्यवाही उन्हीं पक्षों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच हुई हो।
- (C) The evidence must have been published in a government gazette. / साक्ष्य सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुआ होगा ।
- (D) The evidence must have been corroborated by expert opinion. / साक्ष्य की पुष्टि विशेषज्ञ की राय से हुई होगी।

Ans. [B]

13. During a court trial, the defence lawyer objects to the admissibility of certain papers produced as evidence. The judge clarifies that only documents categorized as public documents under the Indian Evidence Act, 1872, can be accepted without strict proof. Which category of documents would fall under public documents in this context? / एक अदालती मुकदमे के दौरान, बचाव पक्ष के वकील ने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत सार्वजनिक दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत दस्तावेजों को ही बिना किसी ठोस सबूत के स्वीकार किया जा सकता है। इस संदर्भ में, किस श्रेणी के दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेजों में शामिल होंगे ?

- (A) Draft agreements between individuals / व्यक्तियों के बीच समझौतों का मसौदा
- (B) Personal diaries of government officials / सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत डायरियॉ
- (C) Internal notes of a private company / किसी निजी कंपनी के आंतरिक नोट्स
- (D) Judicial and executive acts of public officers / सरकारी अधिकारियों के न्यायिक और कार्यकारी कार्य

Ans. [D]

14. Which condition must be satisfied for things said or done by one conspirator to be admissible against others under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 ? / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत एक षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातों को दूसरों के विरुद्ध स्वीकार्य होने के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए ?

- (A) The statement must be made after the conspiracy has ended / बयान षड्यंत्र समाप्त होने के बाद दिया जाना चाहिए
- (B) The statement must involve unrelated matters of personal benefit / बयान में व्यक्तिगत लाभ के असंबंधित मामले शामिल होने चाहिए

Page-3

(C) There must be reasonable ground to believe a conspiracy exists / यह मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि षड्यंत्र मौजूद है

(D) There must be proof that each conspirator personally committed the act / यह प्रमाण होना चाहिए कि प्रत्येक षड्यंत्रकारी ने व्यक्तिगत रूप से कृत्य किया है

Ans. [C]

15. As per Section 30 of Code of Criminal Procedure, 1973, if a Magistrate sentenced a person to two years' imprisonment and a fine, what is the maximum imprisonment he may impose in default of payment of the fine ? / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 30 के अनुसार, यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को दो वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाता है, तो जुर्माना न चुकाने पर वह अधिकतम कितनी कारावास की सजा दे सकता है ?

- (A) 1 year / 1 वर्ष
- (B) 2 years / 2 वर्ष
- (C) 6 months / 6 महीने
- (D) 3 months / 3 महीने

Ans. [C]

16. As per the Constitution of India, after the 86th Constitutional Amendment, which directive principle was modified to ensure early childhood care and education below the age of six ? / भारतीय संविधान के अनुसार, 86वें संविधान संशोधन के बाद, छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नीति निदेशक सिद्धांत (तत्त्व) को संशोधित किया गया था ?

- (A) Article 39 / अनुच्छेद 39
- (B) Article 41 / अनुच्छेद 47
- (C) Article 47 / अनुच्छेद 41
- (D) Article 45 / अनुच्छेद 45

Ans. [D]

17. According to the Code of Civil Procedure, 1908, who can direct the Court that passed the decree to take security when an execution order is challenged in appeal? / सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार, जब किसी निष्पादन आदेश को अपील में चुनौती दी जाती है, तो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को सुरक्षा लेने का निर्देश कौन दे सकता है ?

- (A) Only the High Court exercising writ jurisdiction that is responsible / केवल याचिका अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय
- (B) The Appellate Court hearing the appeal / अपील की सुनवाई करने वाला अपीलीय न्यायालय
- (C) The District Registrar of Property Records / संपत्ति अभिलेखों का जिला रजिस्ट्रार

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs

www.LinkingLaws.com

Linking Laws Tansukh Sir

Get Subscription Now

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



(D) The Police Authority of the concerned jurisdictionum / संबंधित अधिकारिता का पुलिस प्राधिकारी

Ans. [B]

18. Under the Code of Civil Procedure, 1908, how many High Court Judges constitute the judicial membership of the Rule Committee? / सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत, कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियम समिति की न्यायिक सदस्यता का गठन करते हैं ?

(A) Three Judges of the High Court / उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश

(B) Two Judges of the High Court / उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश

(C) Four Judges of the High Court / उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीश

(D) Five Judges of the High Court / उच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीश

Ans. [A]

19. According to The Copyright Act, 1957, what is ordinarily the maximum punishment for copyright infringement under Section 63? / प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) अधिनियम, 1957 के अनुसार, धारा 63 के अंतर्गत कॉपीराइट उल्लंघन के लिए सामान्यतः अधिकतम सजा क्या है ?

(A) Imprisonment up to three years and fine up to two lakh rupees / तीन वर्ष तक का कारावास और दो लाख रुपये तक का जुर्माना

(B) Imprisonment up to two years and fine up to one lakh rupees / दो वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना

(C) Imprisonment up to five years and fine up to three lakh rupees / पाँच वर्ष तक का कारावास और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना

(D) Imprisonment up to seven years and fine up to five lakh rupees / सात वर्ष तक का कारावास और पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना

Ans. [A]

20. As per the Constitution of India, a linguistic community in India seeks to preserve its unique script and literature. Which constitutional provision guarantees them the right to conserve the same? / भारतीय संविधान के अनुसार, भारत में एक भाषाई समुदाय अपनी विशेष लिपि और साहित्य को संरक्षित रखना चाहता । कौन-सा संवैधानिक प्रावधान उन्हें इसके संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है?

(A) Article 28(1) / अनुच्छेद 28 (1)

(B) Article 29 (1) / अनुच्छेद 29 (1)

(C) Article 30 (2) / अनुच्छेद 30 (2)

(D) Article 32 / अनुच्छेद 32

Ans. [B]

21. Under Section 58 of the Code of Civil Procedure, 1908, what is the maximum period of detention in civil prison for a decree amount exceeding ₹ 5,000? / सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 58 के अंतर्गत ₹ 5,000 से अधिक की डिक्री राशि के लिए सिविल जेल में हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है ?

(A) Six weeks / छह सप्ताह

(B) Two months / दो महीने

(C) Three months / तीन महीने

(D) Six months / छह महीने

Ans. [C]

22. Which of the following situation falls within Section 58 (1) (b) of the Code of Civil Procedure, 1908? / निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 58 (1) (b) के अंतर्गत आती है ?

(A) Decree for ₹ 1,800, detention up to three months / ₹1,800 की डिक्री, तीन महीने तक की हिरासत

(B) Decree for ₹3,500, detention up to six weeks / ₹3,500 की डिक्री, छह सप्ताह तक की हिरासत

(C) Decree for ₹ 6,200, detention up to six months / ₹6,200 की डिक्री, छह महीने तक की हिरासत

(D) Decree for ₹ 10,000, detention up to one year / ₹ 10,000 की डिक्री, एक वर्ष तक की हिरासत

Ans. [B]

23. A civil suit is filed against Ajay, and the court issues summons requiring him to appear. After receiving the summons, Ajay consults his lawyer to understand the timeline for filing his written statement of defence under the Code of Civil Procedure, 1908. Within how many days from the date of service of summons must he submit his written statement? / अजय के विरुद्ध एक दीवानी वाद दायर किया गया है और न्यायालय उसे उपस्थित होने के लिए समन जारी करता है। समन प्राप्त होने के बाद, अजय अपने वकील से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत अपने बचाव में लिखित बयान दाखिल करने की समय-सीमा समझने के लिए परामर्श करता है। समन की तामील की तिथि से कितने दिनों के भीतर उसे अपना लिखित बयान प्रस्तुत करना होगा ?

(A) Thirty days / तीस दिन

(B) Fifteen days / पंद्रह दिन

(C) Sixty days / साठ दिन

(D) Ninety days / नब्बे दिन

Ans. [A]

24. How long does the registered address furnished under Section 14A (1) of the Code of Civil Procedure, 1908, remain valid if not changed? / सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 14A (1) के अंतर्गत दिया गया पंजीकृत पता, यदि परिवर्तित न किया जाए, तो कितने समय तक वैध रहता है ?

(A) Six years after final determination of the cause / मामले के अंतिम निर्धारण के छह वर्ष बाद

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOS

 www.LinkingLaws.com

 Linking Laws Tansukh Sir

 Get Subscription Now



(B) Three years after the institution of the suit / वाद प्रस्तुत करने के तीन वर्ष बाद
 (C) Two years after final determination of the cause / मामले के अंतिम निर्धारण के दो वर्ष बाद
 (D) Five years from the date of decree / डिक्री की तिथि से पाँच वर्ष

Ans. [C]

25. According to Section 25 (a) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, what happens if the claimant fails to submit his statement of claim without sufficient cause? / माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 25 (a) के अनुसार, यदि दावेदार पर्याप्त कारण के बिना अपना दावा विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो क्या होगा ?
 (A) The tribunal adjourns the case indefinitely / अधिकरण मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है।
 (B) The tribunal imposes a penalty but continues proceedings / अधिकरण जुर्माना लगाता है, लेकिन कार्यवाही जारी रखता है।
 (C) The tribunal assumes the claim is admitted / अधिकरण यह मान लेता है कि दावा स्वीकार कर लिया गया है।
 (D) The tribunal terminates the proceedings / अधिकरण कार्यवाही समाप्त कर देता है।

Ans. [D]

26. If a case is transmitted to the Central Government under Section 10 of the Special Marriage Act, 1954, what is the time limit for solemnizing the marriage after its decision? / यदि कोई मामला विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 10 के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रेषित किया जाता है, तो उसके निर्णय के पश्चात विवाह संपन्न कराने की समय सीमा क्या है ?
 (A) One month / एक माह
 (B) Two months / दो माह
 (C) Six months / छह माह
 (D) Three months / तीन माह

Ans. [D]

27. What is the maximum term of imprisonment prescribed under Section 31 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 for breach of protection order? / घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 31 के तहत संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए कारावास की अधिकतम अवधि क्या है ?
 (A) Six months / छह महीने
 (B) One year / एक वर्ष
 (C) Two years / दो वर्ष
 (D) Three years / तीन वर्ष

Ans. [B]

28. Under which provision of the Indian Constitution can a Public Interest Litigation

(PIL) be filed directly in the Supreme Court? / भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत जनहित याचिका (PIL) सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है ?
 (A) Article 21 / अनुच्छेद 21
 (B) Article 32 / अनुच्छेद 32
 (C) Article 226 / अनुच्छेद 226
 (D) Article 14 / अनुच्छेद 14

Ans. [B]

29. Under the Land Acquisition Act, 1894, what is the minimum period that must elapse between the publication of notice and the appearance of persons interested before the Collector? / भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत, नोटिस के प्रकाशन और कलेक्टर के समक्ष हितबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति के बीच न्यूनतम कितनी अवधि बीतनी चाहिए ?
 (A) Not less than 7 days / 7 दिनों से कम नहीं
 (B) Not less than 60 days / 60 दिनों से कम नहीं
 (C) Not less than 15 days / 15 दिनों से कम नहीं
 (D) Not less than 30 days / 30 दिनों से कम नहीं

Ans. [C]

30. Under which provision can a citizen file a public case in the Court of Magistrate regarding issues of public interest? / किस प्रावधान के तहत कोई नागरिक जनहित के मुद्दों के संबंध में मजिस्ट्रेट की अदालत में सार्वजनिक मामला दायर कर सकता है ?
 (A) Section 302 of the Indian Penal Code / भारतीय दंड संहिता की धारा 302
 (B) Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144
 (C) Section 133 of Code of Criminal Procedure, 1973 / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133
 (D) Section 482 of Code of Criminal Procedure, 1973 / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482

Ans. [C]

31. According to Section 44AA (2) (i) of the Income tax Act, 1961, a person carrying on business must maintain books of account if income from business or profession exceeds: / आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AA(2)(i) के अनुसार, व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को खाताबही रखनी होगी यदि व्यवसाय या पेशे से आय निम्नलिखित से अधिक है :
 (A) ₹1,20,000
 (B) ₹50,000
 (C) ₹ 5,00,000
 (D) ₹10,00,000

Ans. [A]

32. Under the Patents Act, 1970, which situation prevents a patent application from being published even after the expiry of the prescribed period? / पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत, कौन-सी स्थिति

[Click Here to By Linking Publications](#)





किसी पेटेंट आवेदन को निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी प्रकाशित होने से रोकती है ?

- (A) When the applicant has filed a request for early examination. / जब आवेदक ने शीघ्र परीक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया हो ।
- (B) When secrecy direction is imposed under Section 35. / जब धारा 35 के अंतर्गत गोपनीयता निर्देश लागू किया गया हो ।
- (C) When the patent has already been granted by the Controller. / जब नियंत्रक द्वारा पेटेंट पहले ही प्रदान कर दिया गया हो ।
- (D) When the applicant has requested for an extension of time. / जब आवेदक ने समय विस्तार का अनुरोध किया हो ।

Ans. [B]

33. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). / नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A): Any person having an interest in a newspaper declared forfeited, may apply to the High Court to set aside the declaration within two months of its publication in the Official Gazette. / अभिकथन (A) : किसी समाचार पत्र में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसे जब घोषित कर दिया गया है, राजपत्र में प्रकाशन के दो महीने के भीतर उस घोषणा को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

Reason (R): The Special Bench of the High Court to hear such applications must always consist of exactly three judges, regardless of the strength of that High Court. / कारण (R) : ऐसे आवेदनों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय की विशेष पीठ में हमेशा ठीक तीन न्यायाधीश होने चाहिए, चाहे उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी भी हो ।

In the context of the above assertion and reason under the Code of Criminal Procedure, 1973, which one of the following is correct? / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत उपर्युक्त अभिकथन और कारण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

- (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A). /(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A). /(A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) (A) is true, but (R) is false. /(A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
- (D) (A) is false, but (R) is true. /(A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

Ans. [C]

34. Read the following statements and choose the correct option. / निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।

Statement 1: Under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, admissions are generally relevant and may be proved against the person making them, but cannot ordinarily be proved by or on behalf of that person. / कथन 1 : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत, स्वीकृतियाँ सामान्यतः प्रासंगिक होती हैं और उन्हें देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

Statement 2: An admission can still be proved on behalf of the person making it if it relates to the existence of a state of mind or body, made at or about the time when such condition existed, and is supported by conduct showing its truthfulness. / कथन 2: कोई स्वीकृति उसे देने वाले व्यक्ति की ओर से तब भी सिद्ध की जा सकती है यदि वह मन या शरीर की किसी ऐसी दशा के अस्तित्व से संबंधित हो, जो उस समय या उसके लागभग की हो जब ऐसी दशा विद्यमान थी, और उसकी सत्यता दर्शने वाले आचरण द्वारा समर्थित हो ।

In the context of the above statements under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, which one of the following is correct? / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन - सा सही है ?

- (A) Both Statements 1 and 2 are false / कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं।
- (B) Only Statement 1 is true / केवल कथन 2 सत्य है।
- (C) Only Statement 2 is true / केवल कथन 1 सत्य है।
- (D) Both the Statements are true / दोनों कथन सत्य हैं।

Ans. [D]

35. Which type of allowance qualifies for deduction under Section 16(ii) of the Income-tax Act, 1961? / आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 (ii) के अंतर्गत किस प्रकार का भत्ता कटौती के लिए योग्य है ?

- (A) House Rent Allowance granted by private companies / निजी कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता।
- (B) Entertainment Allowance granted to government employees / सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला मनोरंजन भत्ता।
- (C) Transport Allowance provided to all salaried persons / सभी वेतनभोगी व्यक्तियों को दिया जाने वाला परिवहन भत्ता।
- (D) Leave Travel Allowance given for domestic travel / घरेलू यात्रा के लिए दिया जाने वाला अवकाश यात्रा भत्ता।

Ans. [B]





36. Read the given statements and choose the correct option. / दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए।

Statement 1 : Under the Negotiable Instruments Act, 1881, a negotiable instrument made, drawn, accepted, or transferred without consideration creates no obligation of payment between the parties to the transaction. / कथन 1 : परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत, बिना प्रतिफल के निर्मित, आहरित, स्वीकृत या हस्तांतरित परक्राम्य लिखत, लेन-देन के पक्षों के बीच भुगतान का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करता है।

Statement 2: According to the same Act, if the consideration for which a negotiable instrument was issued fails in part, the holder in immediate relation is entitled to recover only the proportionate amount corresponding to the consideration actually received. / कथन 2 : इसी अधिनियम के अनुसार, यदि वह प्रतिफल जिसके लिए परक्राम्य लिखत जारी किया गया था, अंशिक रूप से विफल हो जाता है, तो निकटतम संबंध में धारक केवल वास्तव में प्राप्त प्रतिफल के अनुरूप आनुपातिक राशि ही वसूल करने का हकदार होता है।

In the context of the above statements under the Negotiable Instruments Act, 1881, which one of the following is correct? / परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(A) Both Statements 1 and 2 are false / कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं
 (B) Only Statement 1 is true / केवल कथन 1 सत्य है
 (C) Only Statement 2 is true / केवल कथन 2 सत्य है
 (D) Both the Statements are true / दोनों कथन सत्य हैं

Ans. [D]

37. In the following question, a statement is followed by two Conclusions, I and II. anoth / निम्नलिखित प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं।

Statement : / कथन:

Under the Environment (Protection) Act, 1986, when an offence is committed by a company, every person who was directly in charge of and responsible to the company at the time of the offence, as well as the company itself, is deemed guilty. However, a person may escape liability if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent it. / पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, जब किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो अपराध के समय कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, साथ ही स्वयं कंपनी, दोषी मानी जाती है। हालांकि, कोई व्यक्ति दायित्व से बच सकता है यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इसे रोकने के लिए उचित तत्परता बरती थी।

Conclusions : / निष्कर्ष :

I. A company as well as its responsible officers may be held liable for environmental offences under the Act. / अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरणीय अपराधों के लिए कंपनी और उसके उत्तरदायी अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

II. An officer of a company can never escape liability once the company is found guilty of an offence. In the context of the above Statement and Conclusions under the Environment (Protection) Act, 1986, which one of the following is correct? / एक बार कंपनी के किसी अपराध के दोषी पाए जाने पर कंपनी का कोई अधिकारी दायित्व से कभी नहीं बच सकता। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपर्युक्त कथन और निष्कर्षों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) Only Conclusion I follows / केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है
 (B) Only Conclusion II follows / केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है
 (C) Both Conclusions I and II follow / (C) निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं
 (D) Neither Conclusion I nor II follows / न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है

Ans. [A]

38. Under Section 24(a) of the Income-tax Act, 1961, what percentage of the annual value of an income from house property is allowed as a standard deduction? / आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 24 (a) के तहत, गृह संपत्ति से आय के वार्षिक मूल्य का कितना प्रतिशत मानक कटौती के रूप में अनुमत है?

(A) 20
 (B) 40
 (C) 30
 (D) 50

Ans. [C]

39. After a government notification is issued for acquiring Mr. Mehta's farmland under the Land Acquisition Act, 1894, he notices that the income from his crops steadily decreases until the authorities finally take possession. He approaches the court claiming compensation for this reduction in profits. According to the Act, what type of loss is compensable in such a case? / भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत श्री मेहता की कृषि भूमि के अधिग्रहण हेतु सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद, उन्हें पता चलता है कि उनकी फसलों से होने वाली आय लगातार कम होती जा रही है, जब तक कि अधिकारी अंततः भूमि पर कब्ज़ा नहीं कर लेते। वे लाभ में इस कमी के लिए मुआवजे की माँग करते हुए अदालत जाते हैं। अधिनियम के अनुसार, ऐसे मामले में किस प्रकार के नुकसान की भरपाई की जा सकती है?

[Click Here to Buy Linking Publications](#)



Scan this
 QR Code to
 Linking Laws BIOS

 www.LinkingLaws.com

 Linking Laws Tansukh Sir

 Get Subscription Now (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



है। बाद में, मकान मालिक पट्टा समाप्त करने का निर्णय लेता है। क्योंकि पट्टा कृषि या विनिर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए है और पक्षों के बीच कोई विशेष अनुबंध नहीं है, इसलिए मकान मालिक यह नहीं समझ पा रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के तहत पट्टा समाप्त करने के लिए उसे कानूनी तौर पर कितने दिनों का नोटिस देना होगा। आवश्यक नोटिस अवधि क्या है ?

- (A) Five days' notice / पाँच दिन का नोटिस
- (B) Fifteen days' notice / पंद्रह दिन का नोटिस
- (C) Forty-five days' notice / पैंतीलास दिन का नोटिस
- (D) Sixty days' notice / साठ दिन का नोटिस

Ans. [B]

40. According to Section 35A of the Code of Civil Procedure, 1908, what is the maximum amount a Court can award as compensatory costs in ordinary cases? / सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35A के अनुसार, सामान्य मामलों में न्यायालय प्रतिकारात्मक खर्च के रूप में अधिकतम कितनी राशि दिला सकता है ?

- (A) ₹2,000
- (B) ₹10,000
- (C) ₹ 5,000
- (D) ₹3,000

Ans. [D]

41. According to the Indian Contract Act, 1872, when is the communication of an acceptance complete against the proposer? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार, प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संप्रेषण कब पूर्ण होता है ?

- (A) When the acceptor prepares the letter of acceptance / जब स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति पत्र तैयार करता है
- (B) When it is dispatched beyond the control of the acceptor / जब इसे स्वीकृतिकर्ता के नियंत्रण से बाहर भेज दिया जाता है
- (C) When it is delivered to the office of the proposer party / जब इसे प्रस्तावक पक्ष के कार्यालय में पहुँचा दिया जाता है
- (D) When the proposer acknowledges receipt in his records / जब प्रस्तावक अपने अभिलेखों में प्राप्ति की स्वीकृति देता है

Ans. [B]

42. Rahul rents a shop in the city for running his retail business. Later, the landlord decides to terminate the lease. Since the lease is for purposes other than agriculture or manufacturing and there is no special contract between the parties, the landlord wonders how many days' notice he must legally give under the Transfer of Property Act, 1882, to end the lease. What is the required notice period? / राहुल अपना खुद का व्यापार चलाने के लिए शहर में एक दुकान किराए पर लेता

43. According to the Negotiable Instruments Act, 1881, what is the maximum sentence of imprisonment that a Magistrate may pass in a summary trial under Section 143? / परकार्य लिखित अधिनियम, 1881 के अनुसार, धारा 143 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण में मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली अधिकतम कारावास की सजा क्या है ?

- (A) Six months' imprisonment / छह महीने का कारावास
- (B) Two years' imprisonment / दो वर्ष का कारावास
- (C) One year's imprisonment / एक वर्ष का कारावास
- (D) Three years' imprisonment / तीन वर्ष का कारावास

Ans. [C]

44. In the following question, a Statement is followed by two Conclusions, I and II. / निम्नलिखित प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं। Statement : / कथन :

As per Section 157 of the Companies Act, 2013 every company must, within fifteen days of receiving intimation under Section 156, furnish the Director Identification Number (DIN) of all its Directors to the Registrar with prescribed fees. Failure to comply attracts penalties. / कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 157 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को धारा 156 के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, अपने सभी निदेशकों की निदेशक पहचान संख्या (DIN) निर्धारित शुल्क के साथ रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर दंड लगाया जा सकता है।

Conclusions : / निष्कर्ष :

- I. If a company fails to furnish the DIN, it can be penalized. / यदि कोई कंपनी DIN प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।
- II. Every officer of the company in default is also liable for penalties. / कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, दंड का भागी भी होगा।

In the context of the above Statement and Conclusions, which one of the following is correct? / उपर्युक्त कथन और निष्कर्ष के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs

 www.LinkingLaws.com

 Linking Laws Tansukh Sir

 Get Subscription Now



- (A) Only Conclusion I follows / केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है
- (B) Only Conclusion II follows / निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं
- (C) Both Conclusions I and II follow / केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है
- (D) Neither Conclusion I nor II follows / न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है

Ans. [C]

45. Read the following Statements related to the Information Technology Act, 2000 and choose the correct option. / सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।

Statement 1 : Under the Information Technology Act, 2000, a Digital Signature Certificate may be suspended by the Certifying Authority on the request of the subscriber, an authorized representative, or if it is considered necessary in the public interest. / कथन 1 : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र को प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा अभिदाता, उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अनुरोध पर, या यदि जनहित में आवश्यक समझा जाए, निलंबित किया जा सकता है।

Statement 2: Under the same Act, a Digital Signature Certificate can remain suspended indefinitely without providing the subscriber an opportunity of being heard. / कथन 2 : इसी अधिनियम के अंतर्गत, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र को अभिदाता को सुनवाई का अवसर दिए बिना अनिश्चित काल तक निलंबित रखा जा सकता है।

- (A) Both Statements 1 and 2 are false / कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं
- (B) Only Statement 1 is true / केवल कथन 1 सत्य है
- (C) Only Statement 2 is true. / केवल कथन 2 सत्य है
- (D) Both the Statements are true / दोनों कथन सत्य हैं

Ans. [B]

46. In the following question, a Statement is followed by two Conclusions, I and II. / निम्नलिखित प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं।

Statement : / कथन:

According to the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, the appropriate Government credits 15,000 to the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund for each child or adolescent for whom the fine amount from the employer has been deposited. The amount in the Fund is deposited or invested in banks, and the interest accrued is also payable to the child or adolescent. / बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, उपर्युक्त सरकार प्रत्येक बच्चे या किशोर के लिए बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष में ₹15,000 जमा करती है, जिसके लिए

नियोक्ता से जुर्माने की राशि जमा की गई है। कोष में राशि बैंकों में जमा या निवेश की जाती है, और अर्जित व्याज भी बच्चा या किशोर को देय होता है।

Conclusions : / निष्कर्ष :

- I. The child or adolescent is entitled not only to the credited amount but also to the interest accrued on it. / बच्चा या किशोर न केवल जमा की गई राशि का, बल्कि उस पर अर्जित व्याज का भी हकदार है।
- II. The Government is not required to deposit any money other than what is collected as fines from the employer. / सरकार को नियोक्ता से जुर्माने के रूप में ली गई राशि के अलावा कोई अन्य धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

In the context of the above Statement and Conclusions, which one of the following is correct? / उपर्युक्त कथन और निष्कर्षों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

- (A) Only Conclusion I follows / केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है।
- (B) Only Conclusion II follows / केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है।
- (C) Both Conclusions I and II follow / दोनों निष्कर्ष I और II अनुसरण करते हैं।
- (D) Neither Conclusion I nor II follows / न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है।

Ans. [A]

47. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). / नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A) : The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, prescribes the death penalty for certain forms of gang rape. / अभिकथन (A) : भारतीय न्याय संहिता, 2023, सामूहिक बलात्कार के कुछ रूपों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करती है।

Reason (R): The purpose of this provision is to make all sexual offences non-bailable. / कारण (R) : इस प्रावधान का उद्देश्य सभी यौन अपराधों को गैर-जमानती बनाना है।

In the context of the above assertion and reason, which one of the following is correct? / उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A) / (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A) / (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) (A) is true, but (R) is false / (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।

[Click Here to By Linking Publications](#)

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs



www.LinkingLaws.com

[Linking Laws Tansukh Sir](#)

[Get Subscription Now](#)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs



www.LinkingLaws.com

[Linking Laws Tansukh Sir](#)

[Get Subscription Now](#)

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India



(D) (A) is false, but (R) is true / (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

Ans. [C]

48. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). / नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A) : Under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, if the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the Court shall release the attached property. / अभिकथन (A) : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत, यदि घोषित व्यक्ति घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होता है, तो न्यायालय कुर्की की गई संपत्ति को मुक्त कर देगा।

Reason (R) : The attachment of property under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 is intended to compel the appearance of the proclaimed person before the Court, not to permanently deprive him of his property. / कारण (R) : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की का उद्देश्य उद्घोषित व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करना है, न कि उसे उसकी संपत्ति से स्थायी रूप से वंचित करना।

In the context of the above assertion and reason, which one of the following is correct? / उपर्युक्त अभिकथन और कारण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A) / (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
 (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A) / (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 (C) (A) is true, but (R) is false / (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
 (D) (A) is false, but (R) is true / (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

Ans. [A]

49. Read the given Statements and choose the correct option. / दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।

A dispute arises between two companies regarding the enforcement of their arbitration clause. Examine the following statements: / दो कंपनियों के बीच उनके मध्यस्थता खंड के प्रवर्तन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। निम्नलिखित कथनों की जाँच कीजिए:

Statement 1: An arbitration agreement must be in writing, and it can be contained in a contract, an exchange of letters, telex, telegrams, or electronic communications. / कथन 1 : एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होना चाहिए, और यह किसी अनुबंध,

पत्रों के आदान-प्रदान, टेलेक्स, टेलीग्राम या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से हो सकता है।

Statement 2 : An arbitration agreement may be implied solely from the conduct of the parties, without any written record. / कथन 2 : एक मध्यस्थता समझौता बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के, केवल पक्षों के आचरण से ही निहित हो सकता है।

(A) Only Statement I is true / केवल कथन 1 सत्य है।
 (B) Only Statement 2 is true / केवल कथन 2 सत्य है।
 (C) Both Statements 1 and 2 are true / कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं।
 (D) Neither Statement 1 nor 2 is true / न तो कथन 1 और न ही 2 सत्य है।

Ans. [A]

50. In the following question, a Statement is followed by two Conclusions, I and II. / निम्नलिखित प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं।

Statement : / कथन:

According to the Advocates Act, 1961, when the term of a State Bar Council expires without an election, the Bar Council of India shall constitute a Special Committee consisting of the ex officio member of the State Bar Council as Chairman and two nominated members. The Special Committee has the power to discharge all functions of the State Bar Council until the new Council is constituted, and elections must be held within six months unless the period is extended by the Bar Council of India. / अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार, जब किसी राज्य बार काउंसिल का कार्यकाल बिना चुनाव के समाप्त हो जाता है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक विशेष समिति का गठन करेगी, जिसमें राज्य बार काउंसिल का पदने सदस्य अध्यक्ष और दो मनोनीत सदस्य होंगे। विशेष समिति को नई काउंसिल के गठन तक राज्य बार काउंसिल के सभी कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार है, और चुनाव करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अवधि बढ़ाई न जाए।

Conclusions : / निष्कर्ष :

I. The Special Committee is empowered to handle pending disciplinary matters of the State Bar Council. / विशेष समिति को राज्य बार काउंसिल के लंबित अनुशासनात्मक मामलों को संभालने का अधिकार है।
 II. The Bar Council of India may extend the six-month period for holding elections to the State Bar Council, for recorded reasons. / बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दर्ज कारणों से, राज्य बार काउंसिल के चुनाव करने के लिए छह महीने की अवधि बढ़ा सकती है।

In the context of the above Statement and Conclusions, which one of the following is correct? / उपर्युक्त कथन और निष्कर्षों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

[Click Here to By Linking Publications](#)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOS



- (A) Only Conclusion I follows / केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है
- (B) Only Conclusion II follows / केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है
- (C) Both Conclusions I and II follow / निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं
- (D) Neither Conclusion I nor II follows / न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है

Ans. [C]

51. Read the given statements and choose the correct option/ दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए ।

Statement 1 : Under the Income tax Act, 1961, a deduction equal to 30% of the actual value is allowed while computing income from house property. / **कथन 1 :** आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, गृह संपत्ति से आय की गणना करते समय वार्षिक मूल्य के 30% के आदर कटौती की अनुमति है।

Statement 2: Where the property has been acquired or constructed with borrowed capital, the maximum deduction for interest payable on such capital is capped at 2,00,000, subject to conditions. / **कथन 2 :** जहाँ संपत्ति उधार ली गई पूँजी से अर्जित या निर्मित की गई है, ऐसी पूँजी पर देय व्याज के लिए अधिकतम कुछ शर्तों के अधीन ₹2,00,000 तक सीमित है।

- (A) Both Statements 1 and 2 are false / कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं
- (B) Only Statement 1 is true / केवल कथन 1 सत्य है
- (C) Only Statement 2 is true / केवल कथन 2 सत्य है
- (D) Both the Statements are true / दोनों कथन सत्य हैं

Ans. [D]

52. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (P). / नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A) : Under the Hindu Succession Act, 1956, a daughter in a Joint Hindu Family governed by Mitakshara Law becomes a coparcener by birth in her own right, just like a son. and / **अभिकथन (A) :** हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में पुरी, पुत्र की भांति जन्म से ही अपने अधिकार से सहादायिक हो जाती है।

Reason (R): This provision grants daughters the same rights, liabilities, and disabilities in coparcenary property as those of sons. / **कारण (R) :** यह प्रावधान पुत्रियों को सहादायिक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार, दायित्व और निर्योग्यताएँ प्रदान करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपर्युक्त अभिकथन

और कारण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ? (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। **In the context of the above assertion and reason under the Hindu Succession Act, 1956, which one of the following is correct? /**

- (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A). / (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है,
- (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A). / (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) (A) is true, but (R) is false. / (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
- (D) (A) is false, but (R) is true. / (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

Ans. [A]

53. As per the Indian Contract Act, 1872, an acceptance must be absolute and unqualified. What is the legal effect if an offeree's response to a proposal introduces a new term? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार, स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव के प्रति प्रस्ताव प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया में कोई नया नियम शामिल हो जाए, तो इसका विधिक प्रभाव क्या होगा ?

- (A) It becomes a valid acceptance, and the new term is incorporated as a mere suggestion. / यह एक वैध स्वीकृति बन जाती है, और नया नियम केवल एक सुझाव के रूप में शामिल हो जाता है।
- (B) It operates as a valid acceptance if the new term is not a material alteration. / यदि नया नियम कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो यह एक वैध स्वीकृति के रूप में कार्य करता है।
- (C) It constitutes a counter-proposal, thereby rejecting the original proposal. / यह एक प्रति-प्रस्ताव का गठन करता है, जिससे मूल प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है।
- (D) It suspends the original proposal until the new term is accepted or rejected by the proposer. / यह मूल प्रस्ताव को तब तक के लिए स्थगित कर देता है जब तक कि प्रस्तावक द्वारा नया नियम स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं कर दिया जाता

Ans. [C]

54. The Indian Contract Act, 1872, provides for specific situations where an agreement without consideration is not void. Which of the following agreements is valid despite the lack of fresh consideration? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 उन विशेष परिस्थितियों का प्रावधान करता है जहाँ बिना प्रतिफल के

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs

 www.LinkingLaws.com

 [Linking Laws Tansukh Sir](#)

 [Get Subscription Now](#)



किया गया समझौता शून्य नहीं होता । निम्नलिखित में से कौन-सा समझौता नए प्रतिफल के अभाव में भी वैध है ?

- (A) An oral promise by 'A' to pay 'B' ₹5000 for a service 'B' voluntarily rendered to 'A' last month. / 'A' द्वारा 'B' को पिछले महीने 'A' को स्वेच्छा से दी गई सेवा के लिए ₹5000 देने का मौखिक वादा ।
- (B) A written and registered promise by a husband, out of natural love and affection, to transfer a / पति द्वारा स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण अपनी पत्नी को संपत्ति हस्तांतरित करने का लिखित और पंजीकृत वादा
- (C) A promise to subscribe ₹ 1 lakh to a public charitable fund. / किसी सार्वजनिक धर्मार्थ निधि में ₹ 1 लाख दान करने का वादा ।
- (D) A promise made by a minor upon attaining majority to pay a debt incurred during his minority. / किसी नाबालिंग द्वारा वयस्क होने पर अपनी अल्पवयस्कता के दौरान लिए गए ऋण को चुकाने का वादा ।

Ans. [A&B]

55. In the context of delegated legislation, the judicial doctrine that prevents a legislature from conferring "uncontrolled legislative power" on the administration is known as the doctrine of: / प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में, वह न्यायिक सिद्धांत जो विधायिका को प्रशासन पर "अनियंत्रित विधायी शक्ति" प्रदान करने से रोकता है, उसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है :

- (A) Ultra Vires / अधिकार - बाह्य (अधिकारातीत)
- (B) Excessive Delegation / अत्यधिक प्रत्यायोजन
- (C) Conditional Legislation / सर्वत विधान
- (D) Separation of Powers / शक्तियों का पृथक्करण...

Ans. [B]

56. For a petition for nullity of marriage under the Hindu Marriage Act, 1955, on the ground that consent was obtained by fraud, what is a statutory bar to granting the decree? / हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विवाह को अमान्य करने के लिए इस आधार पर याचिका दायर की जाती है कि सहमति - धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, तो डिक्टी प्रदान करने में वैधानिक बाधा क्या है ?

- (A) The petition was filed more than six months after the discovery of the fraud. / धोखाधड़ी का पता चलने के छह महीने से अधिक समय बाद याचिका दायर की गई थी ।
- (B) The petitioner has lived with the respondent as husband and wife after the discovery of the fraud. / धोखाधड़ी का पता चलने के बाद से याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहा है।

(C) The fraud relates to the social status of the respondent's family. / धोखाधड़ी प्रत्यर्थी के परिवार की सामाजिक स्थिति से संबंधित है ।

(D) The parties have not attempted reconciliation through a counselling center. / दोनों पक्षों ने परामर्श केंद्र के माध्यम से सुलह का प्रयास नहीं किया है ।

Ans. [B]

57. In the absence of an agreement between the parties, the arbitration proceedings are said to have commenced under Section 21 of The Arbitration and Conciliation Act, 1996: / पक्षकारों के बीच किसी समझौते के अभाव में, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 21 के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही निम्नलिखित तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी:

- (A) on the date of appointment of arbitrator. / मध्यस्थ की नियुक्ति की तिथि पर ।
- (B) on the date the arbitration agreement is signed. / मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि पर ।
- (C) on the date the request for reference is received by the respondent. / प्रत्यर्थी द्वारा मध्यस्थता हेतु अनुरोध प्राप्त होने की तिथि पर
- (D) on the date the arbitral tribunal issues notice. / माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने की तिथि पर ।

Ans. [C]

58. Which of the following public interest litigations expanded Article 21 of the Indian Constitution to include right to enjoyment of pollution-free water and air? / निम्नलिखित में से किस जनहित याचिका ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का विस्तार करके प्रदूषण मुक्त जल और वायु के आनंद के अधिकार को इसमें शामिल किया ?

- (A) Subhash Kumar v. State of Bihar, (1991) 1 SCC 598 / सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, (1991) 1 एससीसी 598
- (B) Nilabati Behera v. State of Orissa, (1993) 2 SCC 746 / नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, (1993) 2 एससीसी 746
- (C) Sheela Barse v. Union of India, (1986) 3 SCC 596 / शीला बरसे बनाम भारत संघ, (1986) 3 एससीसी 596
- (D) Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, (1985) 3 SCC 545 / ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, (1985) 3 एससीसी 545

Ans. [A]

59. Which Public Interest Litigation case resulted in the Supreme Court of India laying down the principle of ' Absolute Liability' ? / किस जनहित

[Click Here to By Linking Publications](#)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs

www.LinkingLaws.com

Linking Laws Tansukh Sir

Get Subscription Now

Page-12

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



याचिका मामले के परिणामस्वरूप भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'पूर्ण दायित्व' का सिद्धांत निर्धारित किया ?

- (A) M.C. Mehta v. Union of India, AIR 1987 SC 1086 / एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, एआईआर 1987 एससी 1086
- (B) M.C. Mehta v. Union of India, 1988 SCR (2) 530 / एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, 1988 एससीआर (2) 530
- (C) M.C. Mehta v. Kamal Nath, (1997) 1 SCC 388 / एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ, (1997) 1 एससीसी 388
- (D) M.C. Mehta v. Union of India, AIR 1997 SC 734 / एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, एआईआर 1997 एससी 734

Ans. [A]

60. In which of the following cases, the Supreme Court of India has pointed out that the rule of *nemo judex in causa sua* is subject to the doctrine of necessity? / निम्नलिखित में से किस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि नेमो जुडेक्स इन कौसा सुआ का नियम आवश्यकता के सिद्धांत के अधीन है ?

- (A) Sahni Silk Mills (P) Ltd. v. Employees' State Insurance Corporation, (1994) 5 SCC 346 / साहनी सिल्क मिल्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम कर्मचारी राज्य बीमा नियम, (1994) 5 एससीसी 346
- (B) In Re: Delhi Laws Act, AIR 1951 SC 332 / इन रे; दिल्ली कानून अधिनियम, एआईआर 1951 एससी 332
- (C) J. Mohapatra & Co. v. State of Orissa, (1984) 4 SCC 103 / जे. महापात्रा एंड कंपनी बनाम उड़ीसा राज्य, (1984) 4 एससीसी 103
- (D) Union of India v. G. Ganayutham, (1997) 7 SCC 463 / भारत संघ बनाम जी. गणयुथम, (1997) 7 एससीसी 463

Ans. [C]

61. As per Section 11 of the Code of Civil Procedure, 1908 for Res Judicata to be applicable on a subsequent suit, the former suit / सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के अनुसार, किसी अनुवर्ती वाद पर रेस ज्युडिकेटा (पूर्व- न्याय) लागू होने के लिए, पूर्ववर्ती वाद

- I. has been finally decided. / अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका होना चाहिए ।
- II. can only be instituted prior to the subsequent suit. / केवल अनुवर्ती वाद से पहले संस्थित किया जा सकता है।
- III. relates to the same matter directly and substantially in issue in the subsequent suit. / अनुवर्ती वाद में सीधे और मूलतः उसी मामले से संबंधित होना चाहिए।

IV. is between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim. / उन्हीं पक्षों के बीच होना चाहिए, या उन पक्षों के बीच होना चाहिए जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करता है।

Select the correct answer. / सही उत्तर चुनें।

- (A) I, II and III
- (B) II, III and IV
- (C) I, III and IV
- (D) I, II, III and IV

Ans. [C]

62. Where the decree is for the payment of money, execution by detention in prison shall not be ordered unless, after giving the judgment-debtor an opportunity of showing cause, the Court is satisfied that the / जहाँ डिक्री धन के भुगतान के लिए है, वहाँ कारावास द्वारा निष्पादन का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि निर्णीत-क्रृष्णी को कारण बताने का अवसर देने के बाद, न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि

- I. judgment-debtor, is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of the Court, / निर्णीत-क्रृष्णी के फरार होने या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को छोड़ने की संभावना है।
- II. judgment-debtor has, before the institution of the suit in which the decree was passed, dishonestly transferred any part of his property. / निर्णीत-क्रृष्णी ने, उस वाद के संस्थित होने से पहले जिसमें डिक्री पारित की गई थी, अपनी संपत्ति का कोई भाग बेर्इमानी से हस्तांतरित कर दिया है।
- III. decree is for a sum for which the judgment-debtor was bound in a fiduciary capacity to account. / डिक्री उस राशि के लिए है जिसके लिए निर्णीत-क्रृष्णी न्यासीय हैसियत से हिसाब देने के लिए बाध्य था।
- IV. judgment-debtor has, or has had since the date of the decree, the means to pay substantial amount of the decree and neglected to pay the same. / निर्णीत-क्रृष्णी के पास, डिक्री की तिथि से, डिक्री की पर्याप्त राशि का भुगतान करने के साधन हैं / थे और उसने उसे भुगतान करने में उपेक्षा की है।

Select the correct answer. / सही उत्तर चुनें।

- (A) I, II and III
- (B) II, III and IV
- (C) I, III and IV
- (D) I, II, III and IV

Ans. [C]

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs

 www.LinkingLaws.com

 Linking Laws Tansukh Sir

 Get Subscription Now (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



63. As per The Code of Civil Procedure, 1908, a decree *ex parte* can be set aside against a defendant / सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार, प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्टी को अपास्त किया जा सकता है

- if he satisfies the Court that the summons was not duly served. / यदि वह न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि समन की तामील विधिवत नहीं की गई थी।
- if he satisfies the Court that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing. / यदि वह न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि वाद की सुनवाई के समय उसे किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था।
- if he satisfies the Court that there has been an irregularity in the service of summons despite the fact that defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim. / यदि वह न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि समन की तामील में अनियमितता हुई है, जबकि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उसके पास उपस्थित होकर वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था।
- without notice being served on the opposite party. / विरोधी पक्ष को सूचना तामील किए बिना।

Select the correct answer. / सही उत्तर चुनें।

(A) I and II
 (B) I, II and III
 (C) I and IV
 (D) I, II, III and IV

Ans. [A]

64. When is a confession made by a person in police custody admissible under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023? / पुलिस हिरासत (अभिरक्षा) में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया संस्वीकृति बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत कब स्वीकार्य होगा?

- Only if it is made voluntarily in writing / केवल तभी जब यह स्वेच्छा से लिखित रूप में दिया गया हो
- Only if it is made in the immediate presence of a Magistrate / केवल तभी जब यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में दिया गया हो
- Only if it is supported by two independent witnesses / केवल तभी जब यह दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित हो
- Only if it is recorded after the charge sheet is filed / केवल तभी जब यह आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दर्ज किया गया हो

Page-14

Ans. [B]

65. Which Section of The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 pertains to opinions of experts? / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की कौन-सी धारा विशेषज्ञों की राय से संबंधित है?

(A) Section 38 / धारा 38
 (B) Section 39 / धारा 39
 (C) Section 36 / धारा 36
 (D) Section 46 / धारा 46

Ans. [B]

66. Which of the following statements is incorrect as per The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023? / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(A) A contracts, in writing, with B, for the delivery of indigo upon certain terms. The contract mentions the fact that B had paid A the price of other indigo contracted for, verbally, on another occasion. Oral evidence is offered that no payment was made for the other indigo. The evidence is admissible. / A, B के साथ कुछ शर्तों पर नील की आपूर्ति के लिए लिखित अनुबंध करता है। अनुबंध में इस तथ्य का उल्लेख है कि B ने किसी अन्य अवसर पर, मौखिक रूप से, अनुबंधित अन्य नील की कीमत A को चुकाई थी। मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य नील के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था। साक्ष्य स्वीकार्य है।

(B) A agrees absolutely in writing to pay B one thousand rupees on 1st March, 2023. The fact that, at the same time, an oral agreement was made that the money should not be paid till 31st March, 2023, can be proved. / A, 1 मार्च, 2023 को B को एक हजार रुपये देने के लिए लिखित रूप से पूर्णतः सहमत होता है। यह तथ्य कि उसी समय, एक मौखिक समझौता किया गया था कि 31 मार्च, 2023 तक धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, सिद्ध किया जा सकता है।

(C) A enters into a written contract with B to work certain mines, the property of B, upon certain terms. A was induced to do so by a misrepresentation of B as to their value. This fact may be proved. / A, B की संपत्ति, कुछ खदानों पर कुछ शर्तों पर काम करने के लिए B के साथ एक लिखित अनुबंध करता है। B द्वारा उनके बारे में गलत जानकारी दिए जाने के कारण A को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया गया था। इस तथ्य को सिद्ध किया मूल्य जा सकता है।

(D) A orders goods from B by a letter in which nothing is said as to the time of payment, and accepts the goods on delivery. B sues A for

[Click Here to Buy Linking Publications](#)



Scan this
 QR Code to
 Linking Laws BIOs



the price. A may show that the goods were supplied on credit for a term still unexpired. / A, B से माल मँगवाने के लिए एक पत्र भेजता है जिसमें भुगतान के समय के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, और माल की सुपुर्दगी पर उसे स्वीकार कर लेता है। B, A पर कीमत के लिए वाद दायर करता है। A यह दर्शित कर सकता है कि माल उधार पर उस अवधि के लिए दिया गया था जो अभी समाप्त नहीं हुई है।

Ans. [B]

67. As per The Hindu Marriage Act, 1955, two persons are said to be within the "degrees of prohibited relationship" if: / हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, दो व्यक्तियों को "प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियाँ" में माना जाता है यदि :

- one is a lineal ascendant of the other, including relationship by adoption. / एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्वपुरुष हो, जिसमें दत्तक नातेदारी भी शामिल है।
- one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of the other, including relationship by half or uterine blood as well as by full blood. / एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो, जिसमें अर्थ या एकोदर रक्त के साथ-साथ पूर्ण रक्त की नातेदारी भी शामिल है।
- one was the wife of the brother or of the father's or mother's brother or of the grandfather's or grandmother's brother of the other. / यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की, या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामह अथवा मातामही के भाई की पत्नी रही हो।
- the two are brother and sister, uncle and niece, aunt and nephew, or children of brother and sister or of two brothers or of two sisters. / यदि वे भाई और बहन, ताया, चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा या भाई-बहन के आपत्य, भाई-भाई के आपत्य अथवा बहन-बहन के आपत्य हों।

Select the correct answer. / सही उत्तर चुनें।

- I, III and IV
- III and IV
- II, III and IV
- MI, II, III and IV

Ans. [D]

68. Which Article of the Constitution of India lays down the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment? /

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है ?

- Article 48A / अनुच्छेद 48A
- Article 39A / अनुच्छेद 39A
- Article 51A(g) / अनुच्छेद 51A(g)
- Article 51A (h) / अनुच्छेद 51A (h)

Ans. [C]

69. The grounds for decree for dissolution of marriage under Section 2 of the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 are that the: / मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 के अंतर्गत विवाह विघटन की डिक्री के आधार हैं

- whereabouts of the husband have not been known for a period of two years. / पति का ठैर-ठिकाना दो वर्षों से जात नहीं है।
- husband has been sentenced to imprisonment for a period of five years. / पति को पाँच वर्ष की अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया गया है।
- husband has failed to perform, without reasonable cause, his marital obligations for a period of two years. / पति दो वर्षों की अवधि के लिए, बिना समुचित कारण के, अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है।
- husband has neglected or has failed to provide for maintenance of his wife for a period of one year. / पति ने एक वर्ष की अवधि के लिए उसकी पत्नी के भरण-पोषण की उपेक्षा की है या उसे प्रदान करने में असफल रहा है।

Select the correct answer. / सही उत्तर चुनें।

- III and IV
- I and II
- I, II, III and IV
- None of these / इनमें से कोई नहीं

Ans. [D]

70. As per The Information Technology Act, 2000, "intermediary", with respect to any particular electronic records, means any person who on behalf of another person receives, stores or transmits that record or provides any service with respect to that record and includes: / सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार, किसी विशेष इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (अभिलेख) के संबंध में "मध्यवर्ती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस रिकॉर्ड (अभिलेख) को प्राप्त करता है, भंडारित करता है या पारेषित करता है या उस रिकॉर्ड (अभिलेख) के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है और उसके अंतर्गत शामिल हैं :

[Click Here to By Linking Publications](#)

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs

[www.LinkingLaws.com](#)

[Linking Laws Tansukh Sir](#)

[Get Subscription Now](#)



- I. telecom service providers. / दूरसंचार सेवा प्रदाता ।
- II. search engines. / सर्च इंजन ।
- III. cyber cafes. / साइबर कैफे ।
- IV. online-auction sites. / ऑनलाइन नीलामी (ऑक्शन) साइट्स ।

Select the correct answer. / सही उत्तर चुनें।

- (A) I and IV
- (B) I and II
- (C) I, II and IV
- (D) I, II, III and IV

Ans. [D]

71. Under Section 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, which of the following orders is not appealable ? / माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा आदेश अपील योग्य नहीं है ?

- (A) Refusing to refer parties to arbitration under Section 8. / धारा 8 के अधीन पक्षों को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने से इंकार करना ।
- (B) Refusing to appoint arbitrator under Section 11. / धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थ नियुक्त करने से इंकार करना ।
- (C) Refusing to grant any measure under Section 9. / धारा 9 के अंतर्गत कोई उपाय को मंजूर करने से इंकार करना ।
- (D) Refusing to grant an interim measure under Section 17. / धारा 17 के अंतर्गत अंतरिम उपाय को मंजूर करने से इंकार करना ।

Ans. [B]

72. Under Section 9A of The Advocates Act, 1961, a legal aid committee constituted by a Bar Council shall consist of : / अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 9A के अंतर्गत, बार कार्यसिल द्वारा गठित विधिक सहायता समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- (A) Not exceeding thirteen but not less than nine members. / तेरह से अधिक नहीं परंतु नौ से कम नहीं।
- (B) Not exceeding eleven but not less than seven members. / ग्यारह से अधिक नहीं परंतु सात से कम नहीं।
- (C) Not exceeding nine but not less than five members. / नौ से अधिक नहीं परंतु पाँच से कम नहीं।
- (D) Not exceeding seven but not less than three members. / सात से अधिक नहीं परंतु तीन से कम नहीं।

Ans. [C]

73. Which Section of the Advocates Act, 1961 provides for the disciplinary powers of the Bar

Council of India ? / अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की कौन सी धारा भारतीय बार कार्यसिल की अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रावधान करती है ?

- (A) Section 35 / धारा 35
- (B) Section 36 / धारा 36
- (C) Section 37 / धारा 37
- (D) Section 380 / धारा 38

Ans. [B]

74. Match List 1 (General Defences in Tort) with List II (Leading Cases) and select the correct answer using the codes given below: / सूची 1 (अपकर्त्य में सामान्य बचाव) को सूची II (प्रमुख मामले) से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर सुनिए :

List I / सूची I	List II / सूची II
i. Act of God / ईश्वरीय कृत्य	1. Vaughan v Taff Vale Rail Co. (1860) 5H & N 679 /
ii. Consent (Folenti non fit injuria) / सहमति (बोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया)	2. Kirby Gregory (1876) 1 Ex, D, 55 / कर्क बनाम ग्रेगरी (1876) 1 एक्स. डी. 55
iii. Statutory Authority / वैधानिक प्राधिकरण	3. Nichols v, Marsland (1876) 2 Ex. D. 1 / निकोल्स बनाम मार्सल (1876) 2 एक्स. डी. 1
iv. Necessity /आवश्यकता	4. Hall v. Brooklands Auto Racing Club (1933) 1 KB 205 / हॉल बनाम ब्रुकलैंड्स ऑटो-रेसिंग बलब (1933) 1 केबी 205

Codes :

- (A) 1-1; ii-2; iii-3; iv-4
- (B) 1-2; 11-3; 11-4; iv 1
- (C) 1-3; i1-4; iii-1; iv-2
- (D) 1- 4; 11 - 1; iii-3; iv-2

Ans. [C]

75. The Central Consumer Protection Council, as provided under Section 3(2) of the Consumer Protection Act, 2019, shall consist of : / उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 3(2) के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (A) a Chairperson and ten other members, or a Chairperson and such other members as may be prescribed. / एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य, या एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किए जा सकते हैं।

[Click Here to By Linking Publications](#)

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs

 www.LinkingLaws.com

 Linking Laws Tansukh Sir

 Get Subscription Now (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



- (B) a Chairperson and five other members. / एक अध्यक्ष और पाँच अन्य सदस्य ।
- (C) a Chairperson and such other members as may be prescribed. / एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किए जा सकते हैं।
- (D) a Chairperson and ten other members. / एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य ।

Ans. [C]

76. In which of the following cases, the Supreme Court of India held that, the Preamble is not part of the Constitution ? / निम्नलिखित में से किस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है ?

- (A) In re: The Kerala Education Bill, 1957, AIR 1958 SC 956 / केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के संबंध में, AIR 1958 SC 956
- (B) Kesavananda Bharati v. State of Kerala, AIR 1973 SC 1461 / केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, AIR 1973 SC 1461
- (C) In re: The Berubari Union and Exchange of Enclaves, AIR 1960 SC 845 / बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव्स के संबंध में, AIR 1960 SC 845
- (D) Minerva Mills Ltd. v. Union of India, AIR 1980 SC 1789 / मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, AIR 1980 SC 1789

Ans. [C]

77. Which Article in the Constitution of India relates to the subject-matter of laws made by Parliament to give effect to treaties and international agreements ? / भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय-वस्तु से संबंधित है ?

- (A) Article 249 / अनुच्छेद 249
- (B) Article 251 / अनुच्छेद 251
- (C) Article 253 / अनुच्छेद 253
- (D) Article 255 / अनुच्छेद 255

Ans. [C]

78. In which of the following judgment/s was the issue of 'right to privacy' dealt with by the Supreme Court of India ? / निम्नलिखित में से किस निर्णय/निर्णयों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'निजता के अधिकार' के मुद्दे पर विचार किया था ?

I. Kharak Singh v. State of Uttar Pradesh & Ors. (AIR 1963 SC 1295) / खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (एआईआर 1963 एससी 1295)

- II. PUCL v. Union of India (AIR 1997 SC 568) / पीयूसीएल बनाम भारत संघ (एआईआर 1997 एससी 568)
- III. Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) & Anr. v. Union of India & Ors. (2017) 10 SCC 1 / न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2017) 10 एससीसी 1
- IV. M.P. Sharma v. Satish Chandra (AIR 1954 SC 300) / एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र (एआईआर 1954 एससी 300)

- (A) II, III and IV
- (B) II and III
- (C) Only III
- (D) I, II, III and IV

Ans. [D]

79. Which of the following actions is required if territory is ceded to any other country by the Union of India ? / यदि भारत संघ द्वारा किसी अन्य देश को कोई क्षेत्र सौंप दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई आवश्यक है ?

- (A) Executive action of the Union of India / भारत संघ की कार्यकारी कार्रवाई
- (B) Presidential proclamation, exercising constitutional power while issuing proclamation / राष्ट्रपति की घोषणा, जिसमें घोषणा जारी करते समय संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है
- (C) Executive action of the Union of India, and then legislative enactment by the Parliament / भारत संघ की कार्यकारी कार्रवाई, और फिर संसद द्वारा विधायी अधिनियमन
- (D) Legislative enactment by the Parliament, and then executive action of the Union of India. / संसद द्वारा विधायी अधिनियमन, और फिर भारत संघ की कार्यकारी कार्रवाई

Ans. [D]

80. The President has referred a question to the Supreme Court and the Supreme Court, as per Article 143 of the Constitution of India, has advised the President accordingly. / राष्ट्रपति ने एक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय को भेजा है और सर्वोच्च न्यायालय ने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार, राष्ट्रपति को तदनुसार परामर्श दिया है।

Can the advice given by the Supreme Court be considered as 'judicial precedent' ? / क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को 'न्यायिक दृष्टान्त / पूर्वनिर्णय' माना जा सकता है ?

- (A) No, because it is not considered as a judgment / नहीं, क्योंकि इसे निर्णय नहीं माना जाता है

[Click Here to Buy Linking Publications](#)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOS

www.LinkingLaws.com

Linking Laws Tansukh Sir

Get Subscription Now



- (B) Yes, because it is considered as a judgment / हाँ, क्योंकि इसे निर्णय माना जाता है
- (C) No, because it is not pronounced in open court / नहीं, क्योंकि इसे खुली अदालत में नहीं सुनाया जाता है
- (D) Yes, because it is pronounced in open court /, क्योंकि इसे खुली अदालत में सुनाया जाता है

Ans. [A]

81. In a criminal trial of defamation, the trial court, i.e., the High Court, has restrained publication of any news on the given case. Which of the following constitutional powers has been exercised by the High Court while passing given order? / मानहानि के एक आपराधिक मुकदमे में, निचली अदालत, अर्थात् उच्च न्यायालय, ने दिए गए मामले से संबंधित किसी भी समाचार के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। दिए गए आदेश को पारित करते समय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया है ?

- (A) Power to issue the writ of mandamus / परमादेश रिट जारी करने की शक्ति
- (B) Power to issue the writ of prohibition / प्रतिषेध रिट जारी करने की शक्ति
- (C) Inherent power / अंतर्निहित शक्ति
- (D) Residuary power / अवशिष्ट शक्ति

Ans. [C]

82. The Supreme Court of India has declared that 'Right to Information' is a fundamental right of every citizen of India. Which of the following stated provisions is used as source of the fundamental right given by the Supreme Court? / भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि 'सूचना का अधिकार' भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है ?

- (A) Article 19 (1) (b), Constitution of India / भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b)
- (B) Right to Information Act, 2005 mer / सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- (C) Article 19(1) (a), Constitution of India / भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a)
- (D) Article 19(1), Constitution of India and Right to Information Act, 2005, collectively / भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, सामूहिक रूप से

Ans. [C]

83. Which of the following Schedules of the Constitution of India deals with the subject

matter of "Validation of certain Acts & Regulations" ? / भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची 'कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण' के विषय से संबंधित है ?

- (A) Schedule IX / अनुसूची IX
- (B) Schedule III / अनुसूची III
- (C) Schedule V / अनुसूची V
- (D) Schedule XB) / अनुसूची X

Ans. [A]

84. Consider the following statements regarding Article 32 of the Constitution of India : / भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. The Article is silent about the locus standi about who may approach the Supreme Court. / यह अनुच्छेद लोकस स्टैन्डाय बारे में मौन है कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन जा सकता है।
- II. The Article is silent about the opposite party against whom the relief under Article 32 may be granted. / यह अनुच्छेद उस विरोधी पक्ष के बारे में मौन है जिसके विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राहत प्रदान की जा सकती है।
- III. The Article creates room for even a sixth type of writ within its scope. / यह अनुच्छेद अपने दायरे में छठे प्रकार की रिट के लिए भी स्थान प्रदान करता है।

Select the correct answer. / सही उत्तर का चयन कीजिए।

- (A) I is false. / I असत्य है।
- (B) II is false. / II असत्य है।
- (C) III is false. / III असत्य है।
- (D) All Statements are true/ सभी कथन सत्य हैं।

Ans. [D]

85. By virtue of Articles 129 and 215, the Supreme Court of India and the High Courts in the States are courts of record and possess contempt jurisdiction. What is true about the lower Judiciary in the same connection ? / अनुच्छेद 129 और 215 के अनुसार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं और उनके पास अवमानना का क्षेत्राधिकार है। इसी संबंध में निचली न्यायपालिका के बारे में क्या सत्य है ?

- (A) Lower Judiciary has to bear with its contempt. / निचली न्यायपालिका को अपनी अवमानना सहन करनी पड़ती है।
- (B) Lower Judiciary has to complain about its contempt to the Supreme Court of India. /

[Click Here to By Linking Publications](#)

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOS

www.LinkingLaws.com

Linking Laws Tansukh Sir

Get Subscription Now

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



निचली न्यायपालिका को अपनी अवमानना की शिकायत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में करनी पड़ती है।

(C) Lower Judiciary can itself punish the contemnor for having caused its contempt. / निचली न्यायपालिका अवमानना करने वाले को उसकी अवमानना के लिए स्वयं दंडित कर सकती है।

(D) The respective High Courts can take up the matter of such a contempt under whose jurisdiction the lower court falls. / संबंधित उच्च न्यायालय उस अवमानना के मामले पर विचार कर सकते हैं जिसके क्षेत्राधिकार में निचली अदालत आती है।

Ans. [D]

86. The Supreme Court of India in *R. K. Anand v. Registrar, Delhi High Court* (2009) 8 SCC 106 held an advocate guilty of misconduct for: / भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आर. के. आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) 8 एससीसी 106 में एक वकील को निम्नलिखित कदाचार का दोषी ठहराया :

(A) threatening judges and use of abusive language during proceedings. / वॉटसन-निह कॉल्बिट / कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों को धमकाने और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के लिए।

(B) filing false affidavits and making reckless allegations against judges. / झूठे शपथ-पत्र दाखिल करने और न्यायाधीशों के विरुद्ध बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए।

(C) interfering in a criminal trial by attempting to influence a witness. / एक गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करके आपराधिक मुकदमे में हस्तक्षेप करने के लिए।

(D) circulating scandalous pamphlets against a sitting Chief Justice. / एक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध निदनीय पर्वे प्रसारित करने के लिए।

Ans. [C]

87. Match List I with List II and select the correct answer using the codes given below: / सूची को सूची | से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए :

List I /	List II /
i. Legitimacy of children of void and voidable marriages / शून्य और शून्यकरणीय विवाहों से उत्पन्न संतानों की वैधता	1. Section 10, The Hindu Marriage Act, 1955 / धारा 10, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
ii. Punishment of bigamy / द्विविवाह का दंड	2. Section 12, The Hindu Marriage Act, 1955 / धारा 12, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
iii. Judicial separation / न्यायिक पृथक्करण	3. Section 17, The Hindu Marriage Act, 1955 /

	धारा 17, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
iv. Voidable marriages 10 to 04. / शून्यकरणीय विवाह	4. Section 16, The Hindu Marriage Act, 1955 / धारा 16, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

Codes:

(A) 1-3; ii-4; iii-1; iv-2
 (B) 1-4; 1-3; iii-2; iv-1
 (C) 1-4; ii-3; iii-1; iv-2
 (D) -1; ii-2; iii-4; iv-3

Ans. [C]

88. Under the Indian Contract Act, 1872, what happens if the principal debtor leaves part of the debt unpaid and there are two or more co-sureties ? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत, यदि मूल ऋणी, ऋण का कुछ भाग अदा न किया हुआ छोड़ दे तथा दो या अधिक सह- जमानतदार हों, तो क्या होगा ?

(A) The creditor alone bears the unpaid portion of the debt / ऋणदाता अकेले ही ऋण का अदा न किया हुआ भाग वहन करता

(B) The debtor's family becomes liable for the unpaid amount / ऋणी का परिवार अदा न की हुई राशि के लिए उत्तरदायी हो जाता है

(C) The co-sureties share the unpaid portion in equal contribution / सह-जमानती अदा न किए हुए भाग को समान अंश में बाँटते हैं

(D) The entire unpaid portion is to be paid by the surety first approached / सम्पूर्ण अदा न की हुई राशि का भुगतान पहले संपर्क किए गए जमानतदार द्वारा किया जाना है

Ans. [C]

89. Under the Specific Relief Act, 1963, when can a defendant in possession of movable property be compelled to deliver it to the plaintiff ? / विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत, चल सम्पत्ति पर कब्जा रखने वाले प्रतिवादी को उसे वादी को सौंपने के लिए कब बाध्य किया जा सकता है ?

(A) When the property is held as agent or trustee of the plaintiff / जब संपत्ति वादी के एजेंट या ट्रस्टी के रूप में रखी जाती है

(B) When the property is held as mortgaged asset of the plaintiff / जब संपत्ति वादी की गिरवी रखी गई संपत्ति के रूप में रखी जाती है

(C) When the property is held as lessee or sub-tenant of the plaintiff / जब संपत्ति वादी के पटेदार या उप-किरायेदार के रूप में रखी जाती है





(D) When the property is held as co-owner in common with the plaintiff / जब संपत्ति वादी के साथ सह-स्वामी के रूप में रखी जाती है

Ans. [A]

90. Read the following statements and choose the correct option: / निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुरें :

Statement 1 : Under the Administrative Tribunals Act, 1985, a Joint Administrative Tribunal for two or more States exercises the same jurisdiction, powers, and authority as an Administrative Tribunal for those States. / कथन 1 : प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण उन राज्यों के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण के समान अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करता है।

Statement 2 : For the purposes of contempt, a Tribunal exercises powers similar to those of a High Court, and references to "High Court" in the Contempt of Courts Act, 1971 are construed to include such Tribunals. / कथन 2 : अवमानना के प्रयोजनों के लिए, एक अधिकरण उच्च न्यायालय के समान शक्तियों का प्रयोग करता है, और न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में "उच्च न्यायालय" के संदर्भों में ऐसे अधिकरणों को शामिल करने के लिए व्याख्या की जाती है।

In the context of the above statements under the Administrative Tribunals Act, 1985, which one of the following is correct? / प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

(A) Both Statements 1 and 2 are false / कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं
 (B) Only Statement 1 is true / केवल कथन 1 सत्य है
 (C) Only Statement 2 is true / केवल कथन 2 सत्य है
 (D) Both the Statements are true to the loin w / दोनों कथन सत्य हैं

Ans. [D]

91. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). / नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A) : A Money Bill can be introduced only in the House of the People (Lok Sabha) and not in the Council of States (Rajya Sabha). / अभिकथन (A) : धन विधेयक केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य सभा में नहीं।

Reason (R): The Council of States may only make recommendations on a Money Bill within 14

days, but the House of the People may accept or reject them, and in either case, the Bill is deemed to be passed. / कारण (R) : राज्य सभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक पर केवल सिफारिशें कर सकती है, लेकिन लोक सभा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, और किसी भी स्थिति में, विधेयक पारित माना जाता है।

In the context of the above assertion and reason under Article 109 of the Constitution of India, which one of the following is correct? / भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 के अंतर्गत उपर्युक्त अभिकथन और कारण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A). /(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
 (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A). /(A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 (C) (A) is true, but (R) is false. /(A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
 (D) (A) is false, but (R) is true. /(A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

Ans. [B]

92. A company, registered under The Companies Act, 2013, is required to file a declaration of commencement of business before starting operations. The directors ignore this obligation, and the firm commences business activities without filing the declaration. How much penalty can be imposed on the company by the Registrar concerned for such non-compliance? / कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत किसी कंपनी को परिचालन शुरू करने से पहले व्यवसाय प्रारंभ करने की घोषणा दाखिल करनी होती है। निदेशक इस दायित्व की अनदेखी करते हैं और फर्म घोषणा दाखिल किए बिना ही व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू कर देती हैं। इस तरह की गैर-अनुपालन के लिए संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है ?

(A) ₹25,000
 (A) ₹25,000
 (B) 50,000 IRIS
 (C) ₹75,000
 (D) ₹1,00,000

Ans. [B]

93. If multiple offences carry different punishments but it is unclear which one has been committed, how does Section 72 of the Indian Penal Code ensure proportional justice? / यदि कई अपराधों के लिए अलग-अलग दंड का प्रावधान है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Scan this
 QR Code to
 Linking Laws BIOs

 www.LinkingLaws.com

 [Linking Laws Tansukh Sir](#)

 [Get Subscription Now](#)



कौन सा अपराध किया गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 72 अनुपातिक न्याय कैसे सुनिश्चित करती है ?

- (A) By imposing punishment for the offence with the lowest prescribed term सबसे कम निर्धारित अवधि वाले अपराध के लिए दंड लगाकर
- (B) By applying punishment equal to the average of all possible offences / सभी संभावित अपराधों के औसत के बराबर दंड लगाकर
- (C) By leaving the choice of punishment to the prosecuting authority / दंड का विकल्प अभियोजन अधिकारी पर छोड़कर
- (D) By suspending the punishment until further clarification is made / आगे स्पष्टीकरण होने तक दंड को निलंबित करके

Ans. [A]

94. Mr. X owns a bakery where he employs Y, a 16-year-old adolescent. At first, X gives Y every Sunday off as his weekly holiday. After two months, X decides to change the weekly holiday to Wednesday and pastes a notice about this change on the bakery wall. According to the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, this change is : / श्रीमान X एक बेकरी के मालिक हैं जहाँ वे 16-वर्षीय किशोर Y को काम पर रखते हैं। शुरूआत में, X, Y को प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक अवकाश देता है। दो महीने बाद, X साप्ताहिक अवकाश को बुधवार करने का फैसला करता है और इस बदलाव के बारे में बेकरी की दीवार पर एक नोटिस चिपका देता है। वाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, यह बदलाव

- (A) valid, since employers can change the holidays anytime by giving notice. / विधिमान्य है, क्योंकि नियोक्ता किसी भी समय नोटिस देकर छुट्टियों में बदलाव कर सकते हैं।
- (B) invalid, since weekly holidays cannot be altered before completion of at least three months. / अविधिमान्य है, क्योंकि साप्ताहिक छुट्टियों में कम-से-कम तीन महीने पूरे होने से पहले बदलाव नहीं किया जा सकता।
- (C) valid, since the adolescent is given a full day of rest every week. / विधिमान्य है, क्योंकि किशोर को प्रत्येक सप्ताह एक पूरा दिन आराम दिया जाता है।
- (D) invalid, only if the notice is not displayed in the establishment. / केवल तभी अविधिमान्य होगा जब सूचना संस्थान में प्रदर्शित न की गई हो

Ans. [B]

95. Which person will not be treated as a consumer under the definition of the Consumer Protection Act, 2019? / उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की परिभाषा के तहत किस व्यक्ति को उपभोक्ता नहीं माना जाएगा ?

- (A) A person who purchases a refrigerator on instalments for home use. / वह व्यक्ति जो घरेलू उपयोग के लिए किश्तों पर रेफ्रिजरेटर खरीदता है।
- (B) A person who buys a television, partly paid and partly promised, for family use. / वह व्यक्ति जो पारिवारिक उपयोग के लिए आंशिक रूप से भुगातान और आंशिक रूप से वादा किया हुआ टेलीविजन खरीदता है।
- (C) A person who purchases goods for the purpose of resale or for any any commercial / purpose. वह व्यक्ति जो पुनर्विक्रय या किसी व्यावसायिक उद्देश्य से सामान खरीदता है।
- (D) A person who uses furniture bought by a relative with the latter's consent. / वह व्यक्ति जो किसी रिश्तेदार द्वारा खरीदे गए फर्नीचर का उसकी सहमति से उपयोग करता है।

Ans. [C]

96. Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). / नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A) : The President of India has the power to grant pardons, reprieves, respites, or remissions of punishment, or to suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of an offence in cases where the punishment is by a Court Martial or where the sentence is death. / अभिकथन (A) : भारत के राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को क्षमादान, विलंब, राहत या दंड में छूट देने, या दंड को निलंबित करने, माफ करने या लघुकृत करने की शक्ति है, वशर्ते कि दंड सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो या दंड मृत्युदंड हो।

Reason (R): This power under Article 72 overrides and completely nullifies the powers of the Governor to commute or remit a death sentence under State law. / कारण (R) : अनुच्छेद 72 के तहत यह शक्ति राज्य के कानून के तहत मृत्युदंड को माफ करने या लघुकृत करने की राज्यपाल की शक्तियों को रद्द कर देती है।

In the context of the above assertion and reason under Article 72 of the Constitution of India, which one of the following is correct? / भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत उपर्युक्त अभिकथन और कारण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

- (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A). / (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।

[Click Here to Buy Linking Publications](#)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOS



(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A). /(A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 (C) (A) is true, but (R) is false. /(A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
 (D) (A) is false, but (R) is true. /(A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है।

Ans. [C]

97. In the following question, a Statement is followed by two Conclusions, I and II. / निम्नलिखित प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं।

Statement : / कथन :

Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, a Magistrate may issue a protection order to prevent the respondent from committing acts of domestic violence, contacting the aggrieved person, alienating assets or stridhan without permission, or causing harm to her dependents. / घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, एक मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा के कृत्य करने, पीड़ित व्यक्ति से संपर्क करने, बिना अनुमति के संपत्ति या स्त्रीधन को संक्रामित (हस्तांतरित) करने, या उसके आश्रितों को नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए सुरक्षा आदेश जारी कर सकता है।

Conclusions: / निष्कर्ष :

I. A protection order can cover not just physical violence but also financial and emotional aspects of domestic violence. / एक सुरक्षा आदेश न केवल शारीरिक हिंसा, बल्कि घरेलू हिंसा के वित्तीय और भावनात्मक पहलुओं को भी कवर कर सकता है।
 II. The Magistrate has wide powers to restrict the respondent's conduct to safeguard the aggrieved person and her dependents. / मजिस्ट्रेट के पास पीड़ित व्यक्ति और उसके आश्रितों की सुरक्षा के लिए प्रत्यर्थी के आचरण को प्रतिबंधित करने की व्यापक शक्तियाँ हैं।

In the context of the above Statement and Conclusions under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, which one of the following is correct? / घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपर्युक्त कथन और निष्कर्षों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) Only Conclusion I follows / केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है।
 (B) Only Conclusion II follows / केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है।
 (C) Both Conclusions I and II follow / निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं।

(D) Neither Conclusion I nor II follows / न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है।

Ans. [C]

98. According to the Motor Vehicles Act, 1988, which factor determines the jurisdiction of the licensing authority in applying for a driving license? / मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय लाइसेंसिंग प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र किस कारक पर निर्भर करता है?

(A) The place where the applicant has family ancestral property. / वह स्थान जहाँ आवेदक की पारिवारिक पैतृक संपत्ति है।
 (B) The place where the applicant has held a bank account for more than a year. / वह स्थान जहाँ आवेदक का एक वर्ष से अधिक समय से बैंक खाता है।
 (C) The place where the applicant votes in local body elections. / वह स्थान जहाँ आवेदक स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करता है।
 (D) The place where the applicant ordinarily resides or carries on business. / वह स्थान जहाँ आवेदक सामान्यतः निवास करता है या व्यवसाय करता है।

Ans. [D]

99. If a convict sentenced to life imprisonment is being considered for remission fractions under Section 57 of the Indian Penal Code, which equivalent term of years is applied by the court? / यदि आजीवन कारावास की सजा पाए किसी दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के तहत सजा में छूट देने (भिन्नों) पर विचार किया जा रहा है, तो न्यायालय द्वारा कितने वर्षों की समतुल्य अवधि लागू की जाएगी?

(A) Ten years of imprisonment / दस वर्ष का कारावास
 (B) Twenty years of imprisonment / बीस वर्ष का कारावास
 (C) Forty years of imprisonment / चालीस वर्ष का कारावास
 (D) Fifty years of imprisonment / पचास वर्ष का कारावास

Ans. [B]

100. According to the Payment of Gratuity Act, 1972 under what circumstance is the completion of five years of continuous service not mandatory for payment of gratuity to an employee by his employer? / उपदान संदाय (ग्रेचुटी भुगतान) अधिनियम, 1972 के अनुसार, किन परिस्थितियों में किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा ग्रेचुटी भुगतान के लिए पाँच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करना अनिवार्य नहीं है?





- (A) Voluntary resignation from the post by the employee. / कर्मचारी द्वारा पद से स्वैच्छिक त्यागपत्र।
- (B) Dismissal of the employee due to misconduct at work. / कार्यस्थल पर कदाचार के कारण कर्मचारी की बर्खास्तता।
- (C) Death or disablement of the employee due to accident or disease. / दुर्घटना या बीमारी के कारण कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता।
- (D) Transfer of the employee to another department within the same organization. / कर्मचारी का उसी संगठन के किसी अन्य विभाग में स्थानांतरण।

Ans. [C]

**Scan QR code for watching video solution of
AIBE Exam 20th 2025**





LINKING PUBLICATION

is available at

www.LinkingLaws.com >> **Linking Publication**

Linking Charts

-  Diglot Technical Words*
-  Important Sections Marking
-  Easy Way for Legal Meditation
-  Section Linking
-  Keywords Highlight
-  Charts Wall Tapping
-  Major Laws Bird View



All Major Laws Linking Charts
(Set of 5 Charts)
Constitution of India
Civil Procedure Code, 1908
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
Bharatiya Saksha Adhiniyam, 2023
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

New Criminal Major Laws
(Set of 2 Charts)
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
Bharatiya Saksha Adhiniyam, 2023
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

ALL-IN-ONE PAPERATHON®

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams.
Available in English and Hindi Edition



Linking Bare Act

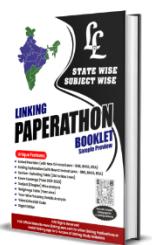
- + Criminal Major Laws 2023 (BNS, BNSS, BSA)
- + Constitution of India + Transfer of Property Act, 1882
- + Criminal Minor Laws + Specific Relief Act, 1963
- + Civil Minor Laws + NDPS Act, 1985
- + CPC, 1908 + PCPNDT Act, 1994
- + Local Laws + Food Safety & Standards Act, 2006
- + Family Laws + Motor Vehicles Act, 1988
- + IT Act, 2000 + Indian Contract Act, 1872
- + A&C Act, 1996 + Labour & Industrial Law
- + Environmental Laws + NI Act, 1881
- + Advocate Act, 1961 + Land Acquisition, 2013 and many more
- + AIBE Additional Bare Acts
- + Consumer Protection Act, 2019



Paperathon® Booklet

Unique Features

1. Sections Switching Table
2. Subject wise Division
3. Cut-Off (Result) Analysis
4. Chapter Wise Bifurcation
5. State Wise PYQ Coverage
6. Subject Weightage Analysis
7. Linked Provision & Explanation
8. Diglot Edition



Paperathon Booklet is
smart analysis of
all questions covered
in previous papers of
judiciary exam.



E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at **Linking App.**   



Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com



Scan this
QR Code to
Linking Laws BIOs

 **Linking Laws Tansukh Sir**

 **Get Subscription Now**

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

15

Institute provide

AI based Smart preparation for